

सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर को सही ठहराया

कहा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक

माला दीक्षित • जागरण

नई दिल्ली: मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग के लिए बुधवार बड़ी जीत का दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर को वैध ठहराया और कहा कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश में जान डालती है। एसआइआर की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। यह लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआइआर प्रक्रिया की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए 124 पृष्ठ का विस्तृत फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता के लिहाज से नागरिकता की जांच करने का सीमित अधिकार है, लेकिन ऐसी जांच कड़े अर्थों में नागरिकता का निर्धारण नहीं मानी जाती। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह

- ▶ यह कहना ठीक नहीं कि प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई
- ▶ मतदाता सूची से नाम हटाने का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं

लोकतंत्र की कहानी वोट देने की ही कहानी नहीं है, बल्कि उनकी पहचान करने की भी कहानी है, जिन्हें सरकार चुनने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। मतदाता सूची उस राजनीतिक समुदाय का कानूनी रिकार्ड होती है। - सुप्रीम कोर्ट

आयोग के दस्तावेज सही

कोर्ट ने एसआइआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा जांच के लिए रखे गए दस्तावेजों को सही ठहराया। कहा कि दस्तावेज एक ऐसे सुसंगत मापदंड पर आधारित हैं जिसका सीधा संबंध मतदाता सूची की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। कोर्ट ने कहा कि वह यह मानने में असमर्थ है कि दस्तावेजों का निर्धारण मनमाना है या वैधानिक योजना का उल्लंघन करता है।

व्यक्ति नागरिक नहीं है। मतदाता सूची में नाम होने से नागरिकता का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सही और उचित जांच के जरिये इस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है।

एसआइआर की वैधता पर मुहर लगाने वाला यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी दल बिहार और बंगाल के विस चुनाव में लगातार एसआइआर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर इसकी आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची



शीर्ष अदालत के समक्ष चार प्रश्न

- ▶ क्या चुनाव आयोग के पास एसआइआर कराने की शक्ति है।
- ▶ क्या एसआइआर वैध उद्देश्य पर आधारित है और क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उस उद्देश्य के अनुपात में है जिसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ▶ क्या एसआइआर में आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून और मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 के प्रविधानों का उल्लंघन करती है।
- ▶ क्या चुनाव आयोग उन लोगों की नागरिकता की जांच कर सकता है जो मतदाता सूची में बने रहने या शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं।

से बाहर करने का आरोप लगा रहे थे। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों में एसआइआर हो चुकी है और बाकी राज्यों में अभी होनी है। इस फैसले से लगता है कि इसकी वैधता पर उठ रहे सवालों का पटाक्षेप हो जाएगा।

जिनके नाम कटे हैं उनके मामले चार हफ्ते में सक्षम अथारिटी को भेजें : वोट देने के अधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि नागरिकता के आधार पर

जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उन सभी मामलों को चार सप्ताह के भीतर नागरिकता कानून के तहत सक्षम अधिकारी को भेजा जाए। सक्षम अधिकारी अगले संसदीय, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले नागरिकता तय करने का काम पूरा कर लेंगे।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता मतदाता सूची की सटीकता पर निर्भर पेज>>5

निजी क्षेत्र की कंपनी बनाएगी पांचवीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान

जागरण न्यूज़ नेटवर्क, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) को नई गति दे दी है। मंत्रालय ने बुधवार को पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप बनाने के लिए शार्टलिस्ट किए गए तीन प्रमुख औद्योगिक समूहों टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और भारत फोर्ज को रिक्वेस्ट फार प्रोजेक्ट (आरएफपी) जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब सरकार ने किसी प्रमुख लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को बाहर रख कर निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया है। इसके लिए लार्सन एंड टुब्रो ने

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, एलएंडटी और भारत फोर्ज शार्टलिस्ट

- ▶ सरकार ने 15 हजार करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इन कंपनियों से मांगी निविदाएं
- ▶ सरकारी कंपनियों का एकाधिकार तोड़ कर निजी क्षेत्र ने लड़ाकू विमानों के निर्माण में हासिल की अहम भूमिका



प्रतीकात्मक

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत फोर्ज ने बीईएमएल के साथ समझौता किया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 15000 करोड़ है।

तेवार होंगे पांच प्रोटोटाइप : ट्रेड के अनुसार शार्टलिस्ट की गई तीनों कंपनियों आने वाले हफ्तों में टेंडर का विस्तृत जवाब रक्षा मंत्रालय को सौंपेंगी। इसके बाद, अगले चार से पांच महीनों के

भीतर अंतिम विजेता का चयन कर लिया जाएगा। चुनी गई कंपनी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) के साथ मिलकर काम करेगी। इस साझेदारी के तहत विमान के कुल पांच प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, जिन्हें परीक्षण और विकास के विभिन्न चरणों से गुजारा जाएगा।

पहली उड़ान 2029 तक

एएनआइ के अनुसार हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फुटफर्ची में इस विमान के लिए 2000 करोड़ से बनने वाले कोर इंटीग्रेशन एंड पलाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी थी। इसके चालू होने के बाद एएमसीए के पहले प्रोटोटाइप के 2027 की शुरुआत तक बनकर तैयार होने जबकि इसकी पहली उड़ान 2029 तक संभावित है।

उभरती सामरिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा एएमसीए : एएमसीए भारतीय वायुसेना की ताकत को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा कर उभरती हुई सामरिक चुनौतियां से निपटने में मदद करेगा। ट्रिवन-इंजन वाले इस लड़ाकू विमान में रडार से बचने वाली अत्याधुनिक स्टेल्थ कॉन्टिंग, हथियारों को छिपाने के लिए इंटरनल वेपन्स बे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर

आधारित प्रणालियां और नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर जैसी कई उन्नत तकनीकें शामिल होंगी। शुरुआती चरण में इसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के जीई-414 इंजन से संचालित किया जाएगा। यह विमान 2035 के बाद वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनेगा।

चीन तेज़ाब कर चुक है स्टेल्थ तकनीक से तैस विमान : चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और चीन पहले से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। पाकिस्तान भी चीन से जल्द ही पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। चीन के अलावा अमेरिका और रूस ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संचालित कर रहे हैं। एएमसीए के परिचालन में आने के बाद भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा।

मंत्रिमंडलीय समिति ने नई 'सार्थक-पीडीएस' योजना को दी मंजूरी

81 करोड़ गरीब समय पर पाएंगे पूरा अनाज

गोदाम से लाभार्थी तक हर चरण की होगी एकीकृत निगरानी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के 81.35 करोड़ गरीबों तक समय पर और पूरी मात्रा में राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी दी है। इस पर पांच वर्षों में 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से राशन वितरण अधिक पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनेगा तथा गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंच सकेगा।

माना जा रहा है कि यदि राज्यों में इसे सही तरीके से लागू किया गया तो राशन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। कालाबाजारी और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी तथा गरीबों को उनका पूरा हक मिलेगा। सरकार भी इसे गरीबों के लिए अधिक भरोसेमंद और आधुनिक राशन व्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।

कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं

5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस योजना पर

31 मार्च, 2031 तक लागू रहेगी केंद्र सरकार की नई योजना

▶ पता चलेगा कि किस राज्य-दुकान में कितना अनाज पहुंचा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए। एएनआइ >>

प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदाम से लेकर अंतिम राशन दुकान और लाभार्थी तक हर चरण की निगरानी एकीकृत तरीके से हो सकेगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस राज्य में कितना अनाज पहुंचा है। किस दुकान पर कितना वितरण हुआ और कहां गड़बड़ी की आशंका है। अभी राशन व्यवस्था दो अलग-अलग योजनाओं के जरिये चल रही है।



पहली योजना में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज उठाकर राज्यों को जिलों, ब्लकों और राशन दुकानों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इसी में उचित मूल्य दुकानदारों का कमीशन भी शामिल है। दूसरी योजना में स्मार्ट पीडीएस के जरिये राशन व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि अलग-अलग योजनाओं में काम होने से समन्वय और निगरानी में दिक्कत आती है। कई राज्यों में व्यवस्था अलग तरीके से चल रही है। अब सरकार ने दोनों

योजनाओं को मिलाकर एक नई एकीकृत व्यवस्था बनाई है, जिसका नाम 'सार्थक-पीडीएस' रखा गया है। यह योजना 31 मार्च, 2031 तक लागू रहेगी। अब राशन व्यवस्था में एआइ, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ब्लाकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। अब सिस्टम खुद पहचान सकेगा कि कहां वितरण धीमा है, कहां अनाज की चोरी हो रही है या कहां फर्जीवाड़े की आशंका है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। राज्यों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पूरे पीडीएस नेटवर्क पर नजर रखी जाएगी। शिकायतों का समाधान एआइ आधारित सिस्टम से होगा। नई व्यवस्था में राशन दुकानदारों और राज्यों को भी राहत मिलेगी। कई राज्यों को एफसीआइ गोदामों से अंतिम वितरण केंद्र तक अनाज पहुंचाने में आर्थिक दिक्कत हो रही थी। अब केंद्र सरकार खर्च में मदद करेगी। साथ ही राशन डीलरों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अंतिम व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना तभी संभव होगा, जब राज्यों और राशन दुकानदारों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। इसलिए नई योजना में वित्तीय सहायता और तकनीकी सुधार दोनों को साथ जोड़ा गया है।

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की

नई दिल्ली, प्रेटर : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की, जो अंतिम परिणाम से पहले पहली बार हुआ है। आयोग ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को कोई आपत्ति हो तो वे 31 मई को शाम छह बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध समर्पित आनलाइन पोर्टल "आनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल (क्यूपीआरईपी)" के माध्यम से अपनी आपत्तियां कर सकते हैं।

आपत्तियां दर्ज करते समय उम्मीदवार को अपनी समझ के अनुसार सही उत्तर कुंजी, संक्षिप्त स्पष्टीकरण और तीन प्रामाणिक स्रोतों से सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, इस साल की प्रारंभिक परीक्षा कई उम्मीदवारों के लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही। ऐसे में आधिकारिक अनंतिम उत्तर कुंजी से बहुत जरूरी स्पष्टता मिलती है। अधिकांश उत्तर मानक पाठ्यपुस्तकों, सरकारी वेबसाइटों, और प्रतिष्ठित

► उम्मीदवार 31 मई शाम छह बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं



फाइल फोटो

समाचार पत्रों पर आधारित होते हैं। ये वे मुख्य स्रोत हैं जिन पर गंभीर उम्मीदवार भरोसा करते हैं। यदि आपको कोई ऐसा उत्तर दिखाई देता है जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है, तो पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। यूपीएससी ने कहा कि उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों को समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की टीमों के समक्ष रखा जाएगा। आयोग की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।

बकरीद आज • गांधी मैदान व जंक्शन जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे नमाज

खुदा के हुक्म पर हजरत इब्राहिम बेटे की कुर्बानी को तैयार हो गए

सिटी रिपोर्टर | पटना

पटना समेत पूरे बिहार व देशभर में 28 मई को बकरीद मनाई जा रही है। ईदुल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। गांधी मैदान समेत सभी खानकाहों, मस्जिदों की कमेटियों ने बकरीद की नमाज के वक्त का ऐलान कर दिया है। गांधी मैदान और पटना जंक्शन जामा मस्जिद में सुबह 7.30 बजे बकरीद की नमाज की तैयारी रही। नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी 28 से 30 मई तक असर की नमाज से पहले तक होगी।

इस्लामिक मामलों के जानकार मौलाना शिबली अल कासमी बताते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने परीक्षा लेने के लिए उनसे सबसे प्यारी चैज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी। खुदा के हुक्म का पालन करते हुए, इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने बेटे की गर्दन पर छुरी चलानी चाही, अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत की याद में हर साल पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं।

सऊदी और खाड़ी के देशों में पढ़ी गई बकरीद की नमाज

इधर, सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में बुधवार को ही बकरीद मनाई गई। बिहार के रहने वाले करीब एक लाख लोगों ने बकरीद की नमाज अदा करने के साथ बिहार में रहने वाले परिवार व रिश्तेदारों को मुबारकबाद दी। जानकार ने बताया कि कुर्बानी हर ऐसे मुस्लिमान पर फर्ज है, जो दसवीं जिल हिज्जा की सुबह को साढ़े सात तोला सोने या साढ़े बावन तोला चांदी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर उसके पास चल या अचल संपत्ति हो। कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त हो। कुर्बानी के जानवरों के लिए उम्र की पाबंदी है। जैसे बकरा, बकरी, भेड़ की उम्र एक साल से कम न हो।

अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं

इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अनीसुर रहमान फरमाते हैं कि कुर्बानी का मूल सिद्धांत अहंकार का त्याग करना है। अल्लाह कुर्बानी में दिखावे या नुमाइश को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के हुक्मों के प्रति समर्पण होना जरूरी है।

राज्यपाल ने दी मुबारकबाद, भाईचारे का दिया संदेश

पटना | राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बकरीद के अवसर पर बिहार और देश के लोगों को मुबारकबाद दी। अपने संदेश में बुधवार को उन्होंने कहा कि यह पर्व अनुपम त्याग और बलिदान का प्रतीक है तथा जीवन में करुणा, कृतज्ञता और मानव सेवा के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे दूसरों के सुख-दुःख में सहभागी बनें, जरूरतमंदों की मदद करें और समाज में प्रेम, भाईचारे व सद्भाव को मजबूत करें। दूसरी ओर, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बकरीद के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग और बलिदान की भावना को मजबूत करता है और समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव तथा मानवीय संवेदनाओं को बढ़ाता है। सभापति ने संदेश में कामना की कि बकरीद का पावन अवसर सभी के जीवन में शान्ति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए।


SC upholds SIR, says it is EC's constitutional duty

Court says EC can verify citizenship for inclusion or exclusion from voter list; it asks poll body to refer names of Bihar electors purged from rolls to Centre for adjudication under Citizenship Act

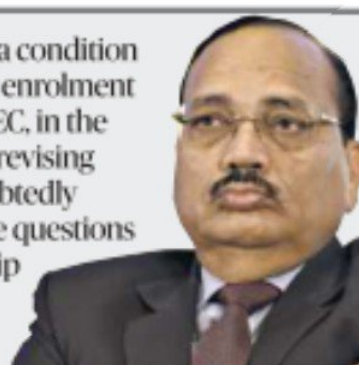
Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday upheld the special intensive revision (SIR) of electoral rolls as an exercise done by the Election Commission (EC) in furtherance of its constitutional obligation to conduct free and fair elections.

"SIR bears a direct nexus to the constitutional goal of a free and fair election. Free and fair elections do not rest merely upon the mechanics of polling. They equally depend upon the integrity, accuracy, and purity of the electoral roll which forms the foundation of the democratic process," a Bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymaya Bagchi said.

 Citizenship is a condition precedent for enrolment [in electoral rolls]. The EC, in the course of preparing or revising electoral rolls, is undoubtedly empowered to examine questions bearing upon citizenship

SURYA KANT
Chief Justice of India



The judgment affirming the constitutionality of the Bihar SIR will have an impact on further rounds of the exercise.

The court dismissed the view of the petitioners that the SIR was a backdoor attempt to conduct citizenship screening in the name of "purifying" the electoral roll of "aliens". The EC was well within its authority to verify citizenship to the limited extent of determin-

ing inclusion or exclusion from the electoral roll, it said. "Citizenship is a condition precedent for enrolment. The EC, in the course of preparing or revising electoral rolls, is undoubtedly empowered to examine questions bearing upon citizenship," Chief Justice Kant, who authored the 124-page judgment, observed.

The court directed the poll body to refer, within

Respectfully disagree: Cong.

NEW DELHI

The Congress on Wednesday said it "respectfully disagreed" with the Supreme Court order upholding the legality of the special intensive revision (SIR) of electoral rolls. » [PAGE 12](#)

the next four weeks, the names of electors who were part of the 2003 electoral roll but were purged in the Bihar SIR on the grounds of being non-citizens, to the Centre for adjudication by a competent authority under the Citizenship Act.

CONTINUED ON
» [PAGE 12](#)

MORE REPORTS ON
» [PAGE 12](#)

Global crises demand more than 'citizen sacrifice'

Recently, Prime Minister Narendra Modi issued seven appeals urging citizens to embrace restraint, self-reliance, and responsible consumption amid global uncertainty caused by the America-Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. These included buying local products, conserving energy, avoiding unnecessary foreign travel, prioritising domestic tourism, supporting indigenous innovation, and promoting work from home wherever feasible.

The appeals have drawn mixed reactions from political parties, economists, businesses, and the public. Some view them as practical nationalism suited to an unstable world, while others see them as realism rather than rhetoric. Supporters argue that promoting domestic consumption and reducing external dependence could strengthen India's resilience in a fractured global economy, while some in the social sector see the messages as supportive of healthier and environmentally sustainable lifestyles.

A subtle shift to the citizen

There is merit in these arguments. India, like every other country, must prepare for a more uncertain global environment. Yet, Mr. Modi's appeals warrant closer scrutiny, as they primarily seek to modify citizen behaviour while leaving governments and institutions relatively insulated from equivalent responsibility. In doing so, the burden of managing structural crises is subtly shifted from the state to individuals.

Modern democratic governance rests on an implicit social contract. Citizens pay taxes, obey laws, participate in democracy, and contribute to the economy. In return, governments are expected to provide public goods, social protection, health care, infrastructure, education, economic stability, and strategic preparedness. Governments exist not merely to advise citizens during crises, but to build systems resilient enough to withstand them. Yet, they often fall short of fulfilling this contract, with even electoral promises only partially implemented before being repackaged for future elections.

When elected governments increasingly respond to structural economic or geopolitical shocks by urging citizens to consume responsibly, sacrifice, adapt, or remain resilient, without simultaneously undertaking matching institutional reforms, the social contract begins to weaken. Long-term opportunities for structural correction are gradually replaced by behavioural messaging and symbolic appeals.

This phenomenon, of course, is not unique to India. Across the world, governments confronting inflation, climate stress, energy insecurity, or economic slowdown routinely ask citizens to reduce consumption, recycle more, conserve electricity, or embrace austerity. Individual behaviour certainly matters. But such appeals often obscure the much larger responsibility of states and corporations in shaping systemic



Chandrakant Lahariya

Practising cardiometabolic physician and health policy specialist who has worked with the United Nations system for nearly 18 years

outcomes. That is why a wider public dialogue and deeper reflection on these issues become essential. Behavioural appeals may generate symbolic solidarity, but symbolism cannot become a substitute for institutional preparedness.

Question for the government

The modern global economy is extraordinarily interconnected. Food security, climate change, financial systems, and technological ecosystems all transcend national borders. No country, including India, can insulate itself through behavioural nationalism alone. The danger lies in oversimplifying complex structural challenges into moral obligations for citizens. Patriotism, however emotionally resonant, cannot replace long-term economic planning, institutional competence, and policy coherence. National resilience is built through capable institutions and sustained public investment.

There is also an uncomfortable asymmetry. Citizens are repeatedly advised to conserve, adjust, and become self-reliant. Yet, why are governments not publicly issuing equivalent commitments to transparency, regulatory stability, public investment, and institutional reform?

Instead of focusing primarily on what citizens should do for governments during crises, one may ask a more foundational democratic question: what should governments do for citizens during periods of global instability? If these seven appeals were reconstructed from a citizen-centric perspective, the priorities would look very different.

First, governments must invest far more seriously in social protection systems. The COVID-19 pandemic showed that resilient societies are built not only through disciplined citizens, but also through strong public institutions. Yet, improvements since then have remained uneven. In health care, the expansion of private and corporate services has often outpaced the strengthening of public systems. Future resilience requires sustained investment in primary health care, disease surveillance, nutrition, mental health, emergency preparedness, education, and other social sectors.

Second, governments must confront rising economic inequality rather than relying excessively on consumption patriotism. Economic resilience cannot emerge from patriotic appeals alone when millions remain financially insecure, unemployed, or trapped within informal labour systems and the gig economy without adequate social protection.

Third, governments must prioritise long-term investments in education, scientific research, and public universities. Genuine self-reliance is built through decades of investment in laboratories, universities, manufacturing ecosystems, scientific temper, and innovation capacity. It is not enough merely to establish Indian campuses of Ivy

League universities; Indian universities and research institutions must themselves emerge as among the world's leading centres of knowledge and innovation.

Fourth, governments must strengthen transparency, public trust, and their handling of widespread public anxiety and uncertainty. During crises, trust becomes a strategic national asset. Citizens cooperate when governments communicate honestly, acknowledge uncertainties, and allow independent institutions, experts, and media to function freely.

Fifth, governments must invest far more seriously in climate resilience and sustainable urbanisation. Asking citizens to conserve electricity while cities continue to suffer from poor planning, inadequate public transport, shrinking green spaces, and worsening environmental degradation addresses symptoms rather than causes. While the push for electric vehicles and alternative energy is welcome, quality urban infrastructure remains inadequate. Failed initiatives such as smart cities are rarely evaluated critically and are instead quietly forgotten.

Sixth, governments must reduce regulatory unpredictability and create stable, fair policy environments for businesses, workers, researchers, and entrepreneurs. National resilience depends upon predictable governance and institutional consistency.

Seventh, governments must protect democratic dialogue instead of allowing criticism to be routinely framed as anti-national. Democracies become stronger through open debate, institutional criticism, intellectual diversity, and democratic course correction.

The need for strong institutions

None of this implies that citizens have no responsibilities. Responsible consumption, environmental awareness, social solidarity, and support for domestic capabilities are important civic virtues. But they cannot substitute for governance itself. Democracies cannot function sustainably if governments merely offer behavioural advice while citizens bear the consequences of structural vulnerabilities.

The larger danger of behavioural politics is that it normalises institutional underperformance. Individual responsibility matters, but it cannot become the primary response to fundamentally structural problems.

India aspires to become a major economic and geopolitical power. Achieving that ambition will require strong institutions, evidence-based policymaking, investment in human capital, and a renewed social contract in which governments accept greater responsibility for national resilience. The true test of leadership during crises is whether governments demonstrate the accountability, foresight, and policy seriousness needed to protect citizens in an increasingly uncertain world.

National resilience requires strong institutions, not merely behavioural appeals alone

The Ebola species with no vaccine

The Bundibugyo ebolavirus outbreak in Congo and Uganda has exposed gaps in vaccine preparedness, with no licensed vaccine yet for the rare species; funding constraints, weak commercial incentives, and limited research investment continue to hamper vaccine development for neglected tropical diseases

FULL CONTEXT

Vasudevan Mukunth

The World Health Organization (WHO) declared the Bundibugyo ebolavirus (BDBV) outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda to be a public health emergency of international concern on May 17.

The outbreak exposes a critical gap in international vaccine preparedness. There is no licensed vaccine yet for the Bundibugyo species of the ebolavirus because the resources required to develop one have not been mustered and because of the specific economic realities of neglected tropical diseases (NTDs).

BSL-4 facilities

To study, develop, and test a vaccine, medical researchers need the virus itself or its genetic sequence to ensure the vaccine's antigens match the circulating strain. In mid-May, the National Institute of Biomedical Research in the Congo and the Central Public Health Laboratories in Uganda delivered this sequence.

Second, to work with a live ebolavirus, scientists need Biosafety Level (BSL) 4 facilities. These are research facilities with the highest level of biological containment, required when dealing with deadly viruses – like ebolavirus and Nipah virus – or viruses that are very easily transmitted or which have no known treatment.

BSL-4 facilities are strongly isolated, with monolithic walls, floors, and ceilings, tightly sealed pipes and wires, multiple sterile rooms with specialised airlocks, negative air pressure (so that a leak causes air to flow into the facility), dedicated ventilation systems, and redundant HEPA filters. All waste from the facility is first sterilised before being disposed of.

Personnel in a BSL-4 facility have to don positive-pressure suits (leak causes air to flow out) and pass through decontamination showers. They also have to undergo rigorous medical tests. There are just over a hundred BSL-4 facilities worldwide, including two in India.

Primate trials

To design the vaccine, researchers need to identify which proteins of the virus provoke the antibody responses in the human body. Then, they need to select a platform – the technology that will carry the antigen into the body and present it to the immune system. The options for ebolavirus include viral vectors such as rVSV or ChAdOx1, mRNA-based approaches, and protein subunits.

Finally, the vaccines may be tested in animal models, in particular non-human primates, as they are the gold standard to assess the safety and efficacy of a vaccine against a disease with a mortality rate of 25% to 90%.

Human clinical trials would be better but such an enterprise would be extraordinarily complicated during an ongoing outbreak.

Once a vaccine is ready, manufacturing it will require hundreds of millions of dollars in addition to development costs, including specialised facilities, cold storage and transport chains (at -80° to -60° C), quality control, regulatory approvals, and advance purchase commitments.

Then, at the very last stage of this long pipeline, healthcare workers and public health officials must detect an outbreak early and administer the vaccine to avail its benefits.



Once a vaccine is ready, manufacturing it will require hundreds of millions of dollars in addition to development costs, including specialised facilities, cold storage and transport chains, quality control, regulatory approvals, and advance purchase commitments. GETTY IMAGES

What 'neglect' means

The ebolavirus is not a single virus species but a genus with multiple species, including 'Zaire', 'Sudan', 'Bundibugyo', and 'Tai Forest'. If a person has become immune to one species, they are not expected to be sufficiently cross-protected against infection by another species. This is because the different species have different surface proteins, so each outbreak may require species-specific research.

Ebolavirus outbreaks are also sporadic and hard to predict as to their location – which is unlike influenza or COVID-19, which circulate continuously in populations. So by the time an ebolavirus vaccine reaches the third phase of a clinical trial, the outbreak may have already subsided, leaving fewer cases to track for the trial.

The commercial market for ebolavirus vaccines is small and concentrated in lower-income countries, which means the financial incentive for pharmaceutical companies to invest without substantial backing from governments and/or coalitions like Gavi and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is minimal.

All of the same factors attend to most NTDs, and illustrate what the 'neglect' in their name entails. NTDs are almost always diseases of poor, rural, and politically marginalised populations in the world's tropical and subtropical areas. In fact, these people are neglected – and that's why their diseases are neglected as well.

Two declarations

Historically, funding for infectious diseases was dominated by just three: HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. The situation changed somewhat following the London Declaration in 2012 and the Kigali Declaration in 2022.

With the participation of the WHO, the World Bank, 13 pharmaceutical companies, and representatives from

seven countries, the London Declaration committed to eliminate or control 10 NTDs by 2020 with more than \$785 million for research and development. The Kigali Declaration, sponsored by Rwanda, aimed to reinvestigate commitments to eliminate the NTDs; at a June 23, 2022, event, the country reported a pledge of \$1.5 billion by various governments, pharmaceutical companies, and NGOs.

However, R&D has often been patchy, compounded by weak healthcare delivery and poor (disease) surveillance. Governments have also often prioritised diseases afflicting patients in richer countries. But the worst is perhaps market failure, as affected populations have little purchasing power while developing a single vaccine these days costs more than a billion dollars. The vaccines also cannot be sold for much in countries most of whose populations live on two dollars a day.

Many NTDs are caused by eukaryotic parasites, i.e. worms and protozoa, which develop in multiple stages across multiple hosts, complicating researchers' efforts to identify a stable antigen for vaccines to target. The immune system also struggles to confer lasting protection against infections by these organisms, making them categorically harder to vaccinate against than, say, measles.

Local response

At this time, there are two licensed Ebolavirus vaccines – Ervebo and a combination of Zabdeno and Mvabea – but they are both for the 'Zaire' species. The Bundibugyo species is also much rarer, having caused only two outbreaks before the current one. As a result, research on it hasn't drawn significant investments.

Promising Bundibugyo vaccine candidates are currently in preclinical or early development, with the WHO and the Oxford Vaccine Group estimating at least six months more to manufacture

enough doses for a small clinical trial.

Taken together, the local healthcare systems – already strained by conflict and climate change – are left with reliably detecting cases, isolating patients, contact-tracing, safe burial practices, and community engagement to manage the Bundibugyo ebolavirus outbreak.

Causes for hope

That said, in the meantime, the Road Map 2021-2030 of the WHO has specified eliminate-by targets for particular NTDs and has been pushing domestically led programmes that combine mass drug administration, vector control, sanitation, and surveillance.

In February this year, the African Union launched 'ACHIEVE Africa', a programme to build indigenous R&D for vaccine development for NTDs that western manufacturers have overlooked. Using the help of such programmes, the African Union plans to manufacture 60% of the continent's vaccine needs by 2040. Likewise, CEPI has increasingly funded work on pathogens that currently present weak commercial incentives.

Also earlier this year, India initiated phase I human clinical trials for an indigenous vaccine against Kyasanur forest disease, a regional NTD. Hubs established in South Africa and Senegal to manufacture mRNA vaccines for COVID-19 are being repurposed to produce experimental vaccines for NTDs, including leishmaniasis.

Brazil and Cuba have built state manufacturing capacity to address diseases that multinational firms have skipped (although this may no longer be a priority in Cuba, which has faced prolonged fuel and medicine shortages thanks to crippling U.S. embargoes).

But for now, the Bundibugyo ebolavirus outbreak continues to unfold against infrastructure and financing gaps and a broader system that struggles to respond to diseases of the poor and the peripheral.

THE GIST

Scientists need BSL-4 facilities and non-human primate trials to safely study and test vaccines against deadly viruses like ebolavirus.

Different ebolavirus species have different surface proteins, meaning immunity against one species may not sufficiently protect against another.

Local healthcare systems are relying on early detection, isolation, contact-tracing, safe burial practices, and community engagement to manage the outbreak.

The battle against AI misinformation

India is working towards Viksit Bharat 2047 with the objective of achieving economic growth, and in order to emerge as a technology leader. One of the major areas that India is concentrating on is the Artificial Intelligence (AI) front. However, a question that needs a definite answer is: what will India's policy be with reference to rapidly developing AI tools? While India's aspiration to attain the status of a global AI hub is commendable, Indian policies regarding AI tools should not only be looked at through the lens of development and economic growth, but also through the lens of growing misinformation and identity manipulation that could be spread through AI platforms.

A new era

ChatGPT recently launched its latest AI multimodal image generation model which has been successful in generating text-heavy images that could rival the work of a professional. Modern generative AI systems are now capable of producing highly sophisticated, text-heavy images akin to a professional newspaper or a scientific research paper. In most cases, these outputs are almost indistinguishable from authentic images taken with the help of a camera, or scanned originals. This model can pull up data from the web portal and provide details of the image with near accurate information.

Thus, through this launch, AI image generation has entered a new era. It is no longer a simple recreational model for a user to dabble with and post on social media platforms to follow a trend; rather, it poses serious concerns in the domain of cyber-crime, theft and digital deceit.

Social networking platforms such as Facebook, Instagram and even LinkedIn are flooded with AI-generated content often leaving users wondering about the veracity of the information they consume. The current version of ChatGPT and similar platforms



Sundar Athreya H.

Assistant Professor at KIIT School of Law, KIIT Deemed to be University, Bhubaneswar



N.S. Amogh Simha

Advocate, Madras High Court and Founder of Ashwin & Amogh Law Chambers, Chennai

While the country seeks to establish itself as a global AI leader, it must develop a robust legal framework that would effectively address the issues of misinformation, identity misuse and manipulation

allow such content to be released disproportionately on social media platforms. Since such platforms are primarily accessed by users through their mobile phones, which have limited screen sizes, the ability to verify such content becomes difficult and users may readily accept AI-generated images posted on these platforms as real.

For instance, a post on LinkedIn about publishing a new research paper, along with the image of the first page of the paper which might contain all necessary details such as the name of the journal and author credentials, might just be fake and non-existent. However, this can be verified by other users only if they check the database; most users are unlikely to fact-check such information.

Educational institutions and genuine academic publishers who strive to maintain originality face challenges as AI systems can fabricate mark sheets, degree certificates and research papers. The persuasive effect of AI-generated content significantly amplifies the possibility of misinformation and manipulation, to the extent where genuine photographs, videos and documents themselves may be dismissed as fabricated thus bearing a large impact on academics, journalism, and institutional credibility.

Various implications

Cybercrimes related to identity thefts have also multiplied in the recent past.

Additionally, celebrities have filed petitions before various High Courts of India seeking protection of their personality rights, and protection against the unauthorised usage of their likeness in image, voice and name using AI. Although various individuals have filed such cases, India has yet to formulate a sound legislative response to this emerging challenge. The implications of AI-generated content also pose risks in terms of

evidence or pleadings that are submitted before courts using AI platforms. The Supreme Court and other High Courts, such as the Bombay High Court, have disparaged such usage and have also imposed costs on lawyers who adopt AI-generated arguments without verifying the submissions and cases cited therein.

Need for regulation

India therefore stands at a critical crossroads at present. While the country seeks to establish itself as a global AI leader, it must develop a robust legal framework that would effectively address the issues of misinformation, identity misuse and manipulation. The challenge at hand is to craft a balanced regulatory framework – one that encourages innovations and technological advancements while simultaneously ensuring accountability from platforms and safeguarding the authenticity of the digital ecosystem.

India's recently amended Information Technology Rules, 2026 mandate the disclosure of AI-generated/ altered content throughout the video. They have also attempted to revamp the age-old intermediary liability framework with the stipulated timeline of three hours to remove synthetically generated content upon receiving a court order or government notification. They also mandate that personal complaints filed by users must be solved within 36 hours of its filing. This is a step in the right direction.

Further, there is a need to develop a code of ethics for AI platforms to prevent them from generating images/videos that would undermine trust in digital news. Beyond the quintessential legal and regulatory frameworks, there is a need for developing digital and AI literacy amongst the public at large. Unless users themselves develop the capacity to critically evaluate a particular digital content and verify the same before dissemination, these issues will continue to linger.